<3) The Cotton Corporation of India has stepped up its purchase operations in ah the cotton growing states Including Gujarat.

(4) Substantial quantities (10.77 lakh bales) of cotton of various varieties have been released by the Govt, for export to foreign countries.

(5) Unlike in the past export quota for staple cotton has also been released in favour of private trade.

(6) With a view to pushing up exports of cotton, the condition of minimum export price for export of cotton has been withdrawn by^fhe Government.

लघु उद्योग क्षेत्रों में रोलर मिलों की स्थापना

@1186-न. **श्री प्यारे लाल खंडेलवाल:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1982 में गेहूं का स्टाक संतोषप्रद न होने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र में रोलर फ्लोर मिल स्थापित करने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) क्या देश में विशेषकर मध्य प्रदेश में हुई गेहूं की बढ़िया फसल को देखते हुए मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े प्रदेशों में गेहूं पर आधारित लघु उद्योग और रोलर मिल स्थापित करने पर लगाये गये प्रतिबन्ध को शिथिल करने पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है ?

योजना मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) (क) यह निर्णय किया गया था कि 24-5-1980 से कोई नयी रोलर फ्लोर मिल स्थापित करने की इजाजत नहीं दी जाएगी ।

(ख) देश में गेहूं की वर्तमान सुगम उपलब्धता को देखते हुए, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 30 मीटरी टन प्रति दिन की क्षमता तक के सीमित संख्या में नये यूनिट लगाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है । राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि इस संबंध में अनुमति प्रदान करने के लिए वे उद्यमियों से 30 अप्रैल, 1986 से पूर्व आवेदन पत्र प्राप्त कर लें और उनपर आगे विचार करने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार को भेज दें । मध्य प्रदेश में नये यूनिट स्थापित करने के लिए प्राप्त हुए अनुरोधों पर इस नीति के अनुसार विचार किया जाएगा ।

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 837, 5 मई, 1986 से स्थानीन्तरित ।

Investment by NRIs

@@U86-C. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the liberalisation measures enforced by the Government have made any effect on the investment made in India during the year 1985-86 by non-resident Indians and other foreign nationals;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether further liberalisation measures are proposed to be introduced to attract foreign investment; if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) and (b) The response of NRIs to the liberalisation measures initiated by Government has been satisfactory as is

©(^Previously Unstarred Question 1036 transferred from 5th May, 1986.